कभी दोनों देशों के बीच बातचीत होगी, तब इस मसले को भी चीन के साथ तय किया जाएगा। इन क्षेत्रों के बारे में कोई प्रादेशिक विवाद नहीं है।

(घ) जी, हां। कैलाश के पश्चिम और मानसरोवर के उत्तर में स्थित भारतीय बस्ती मिनसार में जम्मू तथा काश्मीर सरकार को बहुत समय से कुछ प्रभुत्व अधिकार प्राप्त रहे हैं जिनमें मालगुजारी वसूल करने के अधिकार भी शामिल हैं। हाल के वर्षों में उस बस्ती पर चीनियों द्वारा कब्जा कर लिये जाने के कारण इन अधिकारों का प्रयोग नहीं किय जा सका है और वे अधिकार भी भारत और चीन के बीच के मुख्य विवाद का अंग हैं।

सैनिक ट्रक की दुर्घटना

2912. श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री काशी राम गुप्त :

क्या रक्षा मंत्री 25 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्र न संख्या 4322 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 30 मार्च, 1966 को हुई सैनिक ट्रक दुर्घटना के बारे में रिपार्ट मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन कब मिलने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं। कोर्ट आव इन्क्वायरी की अन्तिम रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोर्ट आव इन्क्वायरी का परिणाम शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

Hunza Principality of Jammu and Kashmir

2913. **Shri Gulshan:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some portion of Hunza Principality of Jammu and Kashmir State has been forcibly occupied by the Chinese Government; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) and (b). Government have seen press reports to this effect. Under the so-called Sino-Pakistan "Agreement" of 1963, Pakistan ceded to China 2050 sq. miles of Indian territory in Pakistan-occupied Kashmir. A portion of this territory belongs to the Hunza Principality (of the State of Jammu and Kashmir) which is under the illegal occupation of Pakistan. Government have no information whether Chinese have forcibly occupied any further territory in Pakistan-occupied Kashmir.

Transfers of Cantonment Officers

2914. **Shri A. N. Vidyalankar:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Industrial Tribunal No. 2 of 1958 had recommended in its Award (Para 24) that the supervisory staff and sectional heads should be transferred from Cantonment to Cantonment and necessary rules were to be framed for the purpose;

(b) whether it is also a fact that no action has so far been taken in this behalf, although nearly six years have elapsed; and

(c) whether Government propose to take any action in this direction and if so, what and when?